

फिर सजेगा निवेश का सबसे बड़ा मंच

योगी सरकार ने शुरू की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की तैयारी, 60 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर नजर

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

यूरो में एक बार फिर निवेश का सबसे बड़ा मंच सजेगा। योगी सरकार ने इस साल की अखिरी गिमाहरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 (GIS) के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। औद्योगिक विकास विभाग एवं इन्वेस्ट यूरो को इसकी कार्ययोजना तैयार करने का कला गवा है। कोशिश यही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में आए निवेश प्रस्तावों के मुकबले डेढ़ से दौगुना निवेश प्रस्ताव हासिल किया जाए। तब यूरो को 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे।

सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने इसे हफ्ते इन्वेस्ट यूरो के कामकाज की समीक्षा को



थी। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान उन्होंने निवेश नीतियों को और सहज बनाने के साथ ही यूरो की संभावनाओं के विस्तार के लिए अगले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए देश-

सरकार को कवाबद केवल निवेश के मेग इवेंट पर ही नहीं बल्कि उसके जमीन पर उठाने की है। 2018 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के 46% से ज्यादा प्रस्ताव तीन ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी के जरिए हकीकत की शकल ले चुके हैं। वहीं, GIS-23 में आए प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए भी एक ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी हो चुकी है जिसे GBC-4 नाम दिया गया था। इसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा के

जमीन पर उतरेंगे और भी प्रॉजेक्ट

निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे थे, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपये का कमर्शल प्रॉडक्शन भी शुरू हो चुका है। आलीं GIS के पहले कुछ और एमओयू को मूर्त रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 3 लाख रुपये करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी भी GIS के पहले की जाएगी। इस तरह 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश भरातल पर उतर चुका होगा।

दुनिया के उद्योगों, निवेशकों से संपर्क-संवाद की संभावनाओं को तलशने पर काम शुरू किया जाएगा।

एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लक्ष्य पर नजर : योगी सरकार ने 8 वर्षों में दो

इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की है। पहली समिट में 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्ताव मिले थे। वहीं, दो साल पहले हुई दूसरी समिट में इसके 10 गुना यानी 40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश



प्रस्ताव आए थे। दोनों ही आयोजन यूरो के औद्योगिक परिवेश के विस्तार के लिहाज से काफी सफल रहे थे। एक करिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रदेश का लक्ष्य एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी

बनना है। इन्वेस्टमेंट इसमें अहम भूमिका निभाएगा। यूरो को मेगा लक्ष्य हासिल करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की जरूरत है। इस साल के अखिर तक इसका एक-तिहाई निवेश

जमीन पा उठाने पर नजर है। आम तौर पर अगर किसी इन्वेस्टर्स समिट में आए एक-तिहाई प्रस्ताव जमीन पर शकल लेते हैं तो इसे अच्छा सफलता माना जाता है। यूरो में यह दर 38% से ज्यादा है। इसे और बढ़ाने पर

फोकस है। इसलिए, अगली GIS में हमारी कोशिश 60 से 80 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रदेश में लाने पर है। इसके लिए नए सेक्टरों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

यू रहा है निवेश का परिवेश

आयोजन
यूरो इन्वेस्टर्स समिट
(21-22 फरवरी 2018)
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
(10-12 फरवरी 2023)

निवेश प्रस्ताव
4.28 लाख करोड़ रुपये
40 लाख करोड़

निवेश जो जमीन पर उतरे

ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी-1
(29 जुलाई 2018)
ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी-2
(28 जुलाई 2019)
ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी-3
(03 जून 2022)
ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी-2
(22 फरवरी 2023)

62 हजार करोड़ रुपये
68 हजार करोड़ रुपये
81 हजार करोड़ रुपये
10.01 लाख करोड़ रुपये

